ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-2* March- 2021
Innovation The Research Concept

राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट 2021–22: विकासोन्मुख एवं प्रगतिशील

Annual budget of Rajasthan Government 2021-22: Development Oriented and Progressive

Paper Submission: 02/03/2021, Date of Acceptance: 23/03/2021, Date of Publication: 25/03/2021

एस. सी. गुप्ता
पूर्व प्रोफेसर,
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार का तीसरा वार्षिक बजट 2021–22 विधानसभा में 24 फरवरी 2021 बुधवार को पहला पेपरलेस डिजीटल बजट 2 घण्टे 46 मिनट में पेश किया। अभी तक विधानसभा में जितने भी बजट पेश किये गये, यह बजट उन सभी में अवधि की दृष्टि से लम्बा था। इस बजट में 47,000 करोड़ रूपये का घाटा रहने का अनुमान है।इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए 295 नई योजनाऐं घोषित की हैं।इस बजट में प्रदेश में कृषि विकास, पशु पालन विकास, मत्स्य व्यवसाय, औद्योगिक विकास, यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधायें, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा, जयपुर शहर का विशेष विकास इत्यादि पर बल दिया गया है।

Honorable Chief Minister of Rajasthan Pradesh Shri Ashok Gehlot ji presented the third annual budget of his government in 2021-22 Vidhan Sabha on 24 February 2021 Wednesday, the first paperless digital budget in 2 hours 46 minutes. So far all the budgets presented in the Vidhan Sabha, this budget was long in terms of duration. In this budget, there is estimated to be a deficit of Rs 47,000 crores.

In this budget, Hon'ble Chief Minister has announced 295 new schemes keeping in mind the needs of the people of the entire geographical area of the state. In this budget, agriculture development, animal husbandry development, fisheries business, industrial development, traffic and means of conveyance in the state. Emphasis has been laid on development of education, health and medical facilities, women and child development, promotion of tourism industries, special development of Jaipur city etc.

मुख्य शब्द : वित्तीय बजट, कोरोना महामारी, जी.डी.पी., राजस्थान।
Annual Budget, CORONA Pandemic, G.D.P., Rajasthan.

प्रस्तावना

राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपनी तीसरी पांच वर्षीय सरकार के इस पांच वर्षीय सरकार का तीसरा वित्तीय बजट वर्ष 2021–2022 के लिए विधानसभा में 24 फरवरी 2021 बुधवार को पहला पेपरलेस डिजीटल बजट पेश किया। यह बजट 2,50,747 करोड़ रूपये काहै जबकि गत वर्ष 2020–21 के लिए 2,25,731 करोड़ रुपये का बजट मुख्यमन्त्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पेश किया गया था। प्रस्तुत बजट में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक घटा होने का अनुमान है।

राजस्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में भी पिछले वर्ष सेकोरोना महामारी से जूझ रही हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना से उभरने के लिए राज्य के काफी आर्थिक और मानव संसाधन उपयोग में लगाये हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी का उत्पादन, रोजगार, जी.डी.पी. इत्यादि बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कोरोना से उभरने का नाम नहीं ले रही है, दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि नजर आ रही हैं इन परिस्थितियों में भी मुख्यमन्त्री जी ने अपने वर्तमान वित्तीय

बजट 2021–22 में 295 नई योजनाओं की जनहित में घोषणा की है, साथ ही पुरानी योजनाओं को भी यथावत जारी रखा है।

प्रस्तुत बजट में प्रदेश में कृषि, उद्योग एवं बुनियादी आवश्यकताओं: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पेयजल, सड़क विकास इत्यादि के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया है, साथ ही प्रत्येक परिवार को 850 रुपये वार्षिक देकर 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ, जनता पर कोई नया कर नहीं, 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा, 50 लाख रुपये तक के फ्लैट की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत, महिलाओं को फ्री सैनेटरी नैपकिन, राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर डिफाल्टर घोषित हो चुके किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेन्ट योजना, राज्य कर्मचारियों की कोरोनाकाल में की गयी वेतन कटौती का भुगतान, ग्राम सेवक, पटवारी व मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5 हजार रूपये का ईनाम, प्रतियोगी परीक्षार्थियों को फ्री रोड़वेज बस सेवा, ग्रामीण बससेवा फिर से कारगर करने, प्रदेश में 352 ब्लॉक में छोटे–छोटे स्टेडियम बनाने, वकीलों के कल्याण कोष में वी.सी.आर. देने, देवस्थान मन्दिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाना इत्यादि घोषणायें मुख्यमन्त्री जी के द्वारा जनहित में की गयी है।

मुख्यमन्त्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत बजट में प्रदेश में मकान खरीदना, इमारती लकड़ी, गुड–चीनी, देशी घी, जौ, उडद, मूंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वातानुकूलित आरामदायक बसों में यात्रा, उपहार डीड, ओवरलोडिंग जुर्माने को 20 हजार रुपये से कम करके 5 हजार रुपये इत्यादि सस्ता/कम किया गया है।

प्रस्तुत बजट में प्रदेश में कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही मुख्यमन्त्री जी ने यह भी घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में अलग से एक कृषि बजट पेश किया जावेगा। प्रदेश में 13 लाख किसानों के लिए एक नई कृषि विद्युत वितरण कम्पनी की स्थापना की जावेगी, इस प्रकार प्रदेश में छः बिजली कम्पनियां हो जावेगी, जो ऊर्जा विभाग के अधीन काम करेगी। भारत में राजस्थान पहला राज्य है जहां 41 प्रतिशत बिजली का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है तथा सरकार पर सबसे अधिक सब्सिडी का बोझ भी यही से आता है। राज्य में बिजली के 13 लाख कृषि उपभोक्ताओं को अब 12 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी प्राप्त होगी, इस घोषणा से उन किसानों के बिजली के बिल शून्य हो जावेंगे जिन्हें वार्षिक 12 हजार रुपये बिजली का खर्च चुकाना पड़ता है बशर्ते उनके बिजली के मीटर सही चलते हों, अन्यथा उन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा करने से सरकार पर 1,450 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार ने प्रत्येक माह के स्थान पर दो माह में बिजली के बिल जारी करने की बात स्वीकार कर ली है। लेकिन यह निर्णय वीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ता (जिनकी बिजली की मांग 150 यूनिट तक हो) व समस्त कृषि विद्युत उपभोक्ता जिनकी संख्या प्रदेश में लगभग 76 लाख है, पर ही लागू होगा। इस बजट में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अन्तर्गत कृषकों के साथ–साथ मत्स्यपालकों व पशुपालकों को भी शामिल किया जावेगा। प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं के लिए बिजली की घरेलू दर की 50 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में 50 हजार सोलर पम्प सैट व 50 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन किसानों को वितरित किये जावेंगे। इस बजट में राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों में किसान सेवा केन्द्र खोले जावेंगे तथा इनके संचालन के लिए 1,000 कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित कर उन पर नियुक्ति की जावेगी। प्रदेश में समस्त कृषि मण्डियों को ऑन लाइन करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये व्यय किये जावेंगे। आगामी तीन वर्षों में ही 4 लाख 30 हजार हैक्टेयर भूमि को सूक्षम सिंचाई योजना के अधीन कृषि के लिए तैयार किया जावेगा। इस बजट में एक लाख किसानों के लिए कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की जावेगी, तीन लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रेंट्स किट का वितरण किया जावेगा, 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज बांटे जावेंगे, 30 हजार कृषकों के लिए डिग्गी व फार्म पौण्ड्स का निर्माण करवाया जावेगा, फॉर्मर, प्रोडयूसर केन्द्रों की स्थापना की जावेगी, इनके साथ ही 1.20 लाख कृषकों को स्प्रिंकल व छोटे स्प्रिंकल वितरित किये जावेंगे। जोधपुर के आंगणवा में आधुनिक सुविधायुक्त ज्योतिराव फूले उपज मण्डी 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जावेगी, भदवासिया में राजमाता विजियाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी 20 करोड़ रुपये की लागत से किसान काम्पलेक्स के नाम से तैयार की जावेगी। राज्य के सभी 33 जिलों में फूड पार्क बनाने की तैयारी है। आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 1,000 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जावेगी। प्रदेश में 48 करोड़ रुपये की लागत से घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा मुहैय्या करवाने के लिए 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा सरकार प्रारम्भ करेगी। प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार प्रीतमपुरी, डूंगरपुर, हिंडोली व हनुमानगढ़ में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करेंगी। राजसमन्द में स्वतन्त्र दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ का गठन किया जावेगा, साथ ही प्रदेश में 1500 दुग्ध संकलन केन्द्र प्राथमिक उत्पादक सहकारी समितियों में क्रमोन्नत किये जावेंगे। गत वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान में लगातार वृद्धि देखने को मिली है।

प्रस्तुत बजट में प्रदेश में स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा के विकास पर 13,309 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है। इसमें से 377 करोड़ रुपये का बजट कॉलेज शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधानहै। मिड डे मील पर 1,061 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है। 7. 50 लाख विद्यार्थियों को आर.टी.ई. के तहत निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। 200 करोड़ रुपये का प्रावधान देवनारायण योजना में पैकेज एम.वी.एस. के लिए 3 छात्रावास खोलने के लिए रखा गया है। 60 करोड़ रूपये की मुफ्त पुस्तकें छात्रों को आगामी वित्त वर्ष में वितरित की जावेगी। प्रदेश में चार नये पॉलोटेक्निक व चार आई.टी.आई. कॉलेजों की स्थापना की जावेगी। सात संस्कृत स्कूलों को क्रमोन्नत किया जावेगा। सैदपुरा–नदबई के संस्कृत स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित

किया जावेगा। बांसवाड़ा में 25 करोड़ रुपये से वैद विद्यापीठ की स्थापना की जावेगी। जोधपुर में फिनटैक डिजिटल विश्वविद्यालय व जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग का डीम्ड विश्वविद्यालय खोला जावेगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को वाई–फाई किया जावेगा। दस नये सरकारी कॉलेज व 12 कन्या कॉलेज खोले जावेंगे। दिवसंगत चारों विधायकों के नाम पर उनके क्षेत्र में कन्या कॉलेज खोले जावेंगे। प्रदेश में श्री राजीव गांधीसेन्टर ऑफ एडवांस्ड टैक्लोलोजी स्थापित किया जावेगा। गत वर्ष स्थापित शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय में विधिवत् कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

आगामी वर्ष में प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक निःशुल्क यूनीफॉर्म, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जावेगी। प्रदेश में 1,200 नये राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जावेंगे। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टी.वी. व सेट टॉप बॉक्स लगवाये जावेंगे। वर्ष 2021–22 में प्रदेश में 600 राजकीय विज्ञान संकाय वाले स्कूलों में कृषि संकाय खोलने की योजना है, इसी प्रकार 3,500 राजकीय स्कूलों में बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने व 15 राजकीय स्कूलों में भवन निर्माण करने की बात बजट में निहित है। प्रस्तुत बजट में 37,400 आंगन बाड़ी केन्द्रों व 134 विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में प्री–प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था के लिए चाइल्ड फ्रेन्डली फर्नीचर जुटाया जावेगा। आगामी वर्ष 2021–22 में प्रदेश में 50 नये राजकीय स्कूल प्रारम्भ किये जावेंगे व 100 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जावेगा।

प्रस्तुत बजट में प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर 10,171 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें जयपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियोलोजी स्थापित किया जावेगा। इसके साथ ही जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेडिसिन एण्ड बायोलॉजी की स्थापना की जावेगी, इससे डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार इत्यादि जैसी बीमारियों का ईलाज, उपचार व शोध होगा। लीवर ट्रांसप्लान्ट के लिए पेनक्रियेटो बिलेरी सर्जरी, गठिया के लिए इम्यूनोलॉजी व कमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरिनरी सम्बन्धी इलाज के लिए पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग और यूरो ओकोलॉजी विभाग की स्थापना आगामी वित्तीय वर्ष में की जावेगी। इस बजट में जयपुर में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए, 200 करोड़ रुपये का प्रावधान टेकनोलॉजी संस्थान के लिए व 40 करोड़ रुपये हाई परफोरमेंस ट्रेनिंग एण्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए रखा गया है। जयपुर में एस.एम.एस. अस्पताल में शोध कार्यों पर बजट वर्ष में विशेष ध्यान दिया जावेगा। जयपुर में सांगानेर में एक नये सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की गयी हैं एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर से सम्बन्धित गणगौरी बाजार में स्थित गणगौरी अस्पताल में बुनियादी आवश्यकताओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में और भी अधिक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जावेगा। इसी प्रकार जोधपुर शहर को कई मेडिकल संस्थानों की सौगात इस बजट में दी गयी है। जोधपुर में इम्यूनोलॉजी–रूमेटोलॉजी, पीडियाट्रिक, यूरोलॉजी विभाग स्थापित किया जावेगा, जोधपुर में अनेक विभाग और अनपेड ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेटरनिटीएण्ड नियोनेटोलॉजी तथा क्षेत्रीय सेन्टर खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज अजमेर कायड़ में स्थानान्तरित होगा, जिसके भवन की लागत 200 करोड़ रुपये आवेगी। प्रदेश में भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर, पाली, चुरु और बाड़मेर में नये अस्पताल भवनों का निर्माण किया जावेगा। कुचामनसिटी, लाडनूं, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं, हलैना, भरतपुर, मनियाँ, कोलायत में 10 नये ट्रोमा सेन्टर खोले जावेंगे व 40 सी.एच.सी. और 25 पी.एच.सी. के भवन तैयार होंगे। राज्य के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जावेगा तथाएक हजार पलंग की सुविधायें बढ़ाई जावेगी। राज्य में 11,000 आयुर्वेद औषधालय स्थापित होंगे तथा हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर भी प्रारम्भ किये जावेंगे।

प्रस्तुत बजट में सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास पर 315.26 करोड़ रुपये व्यय करेगी, जिससे प्रदेश में 64 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जावेंगे। प्रदेश में सरकार सूक्षम, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए नई एम.एस.एम.ई. नीति का अनुसरण करेगी। इसी बजट में 430 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान महिला एवं बाल विकास के लिए रखा गया है। प्रस्तुत बजट में सैलानियों के लिए पर्यटन विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। इस बजट में पर्यटन विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है।

प्रस्तुत बजट के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में जयपुर शहर के विकास पर 700 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है। डिग्गी मालपुरा रोड़ से टोंक रोड़ के बीच सवा लाख आबादी को बीसलपुर योजना का पानी का लाभ प्राप्त होगा। इस कार्य पर लगभग 115 करोड़ रुपये व्यय होंगे। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जेम बूर्स की स्थापना जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और जयपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन करेगी। जयपुर में तीन नये थाने एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर एयरपोर्ट और अजमेर हाईवे पर स्थापित किये जावेंगे। बगरू, बस्सी और चन्दवाजी तक सड़कों को 30 कि.मी. क्षेत्र में जेडीए के द्वारा दुरस्त किया जावेगा। जयपुर शहर को ट्रेफिक की रफ्तार देने के लिए सात चौराहों को सिग्नल से मुक्त रखा जावेगा। एम.एम.एस. स्टेडियम में खिलाड़ियों के रहने के लिए एक आवासीय हॉस्टल का निर्माण किया जावेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. राजस्थान में कृषि विकास
2. राजस्थान में पशुपालन विकास
3. राजस्थान में मत्स्य विकास
4. राजस्थान में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास
5. राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए नई एम.एस.एम.ई. नीति का अनुसरण

6. राजस्थान में यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास
7. राजस्थान में स्कूल, कॉलेज व तकनीकी शिक्षा का विकास
8. राजस्थान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विकास एवं विस्तार
9. राजस्थान में महिला एवं बाल विकास
10. राजस्थान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा
11. राजस्थान में जेम एवं ज्वैलरी उद्योग का विकास

निष्कर्ष

प्रस्तुत बजट में माननीय मुख्यमन्त्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर घोषणाएँ की गयी हैं। इसमें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है। इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस बजट से कोरोना से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो गतिरोध उत्पन्न हो गये हैं उनका भी समाधान निहित है। इस बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, यातायात एवं सन्देश वाहन के साधनों का विकास, रोजगार के अवसर, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि का विकास एवं विस्तार होगा व राज्य की कुल मिलाकर जी.डी.पी. बढ़ेगी। यह एक विकासोन्मुख एवं प्रगतिशील बजट है। इसमें विकास की सकारात्मक सोच निहित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *The Hindustan Times, Jaipur*
2. *The Times of India, Jaipur*
3. *राजस्थान पत्रिका, जयपुर।*
4. *दैनिकभास्कर, जयपुर।*
5. *डेलीन्यूज, जयपुर।*
6. *राष्ट्रदूत, जयपुर।*